RAJYA SABHA

Monday, the 13th July, 1998/ 22 Asadha, 1920 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Strategy to Deal with Sanctions

*361 SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether FICCI have suggested any new strategy to deal with sanctions imposed by the U.S. and Japan as well as the tough stand taken by the European Union;

(b) if so, reaction of Government to FICCI's strategy as reported to have been made in Hindustan Times dated the 19th May, 1998;

(c) whether Government feel that current sanctions if extended/broad based are likely to affect India's industrial growth during 1998-99 and onwards; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) FICCI has not submitted any formal strategy proposal to the Government.

(b) In the news item referred to, the central suggestion was for creation of a multi-disciplinary Think Tank which would evolve new ideas to respond to the effect of the sanctions. Government have already set up a Core Group of Secretaries on Economic Matters which has been constantly assessing the impact of economic sanctions against India with a view to formulating appropriate responses as part of an ongoing exercise.

(c) and (d) On the basis of an independent survey of the effect of sanctions on infrastructure industries, FICCI concluded that projects in the Power sector are not likely to be adversely affected and will be able to raise finances from alternate resources. This survey also indicates that in the Telecom sector, the cost of borrowing might rise. On the whole in the assessment of FICCI, the magnitude of the overall impact of sanctions on Indian industry will not be significant.

Government is closely monitoring the situation to ensure that sanctions have no adverse impact on overall industrial production. Initiatives taken by the Government to encourage foreign direct investment (FDI) and investment by non-resident Indians (NRI) and foreign institutional investors (FII) are also likely to make a positive impact in the direction. India is perceived as a large market and a potentially attractive and growing economy by MNCs. Further, procedures for FIPB approvals have been simplified and more projects have been moved to the automatic approval route. These measures are expected to lead to an increased inflow of foreign direct investment.

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति महोदय, मैंने जो प्रश्न माननीय मंत्री जी के सामने रखा और उन्होंने जो उत्तर दिया, मैं उससे काफी संतुष्ट हूं। लेकिन दो-तीन प्रश्न इससे जरूर खड़े होंगे। यद्यपि यह बात सही है कि पोखरण में आणविक शक्ति के प्रदर्शन के बाद कई राष्ट्रों ने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बड़े जोर-शोर से घोषणाएं की थी लेकिन भारत सरकार ने उन सभी राष्ट्राध्यक्षों को, संबंधित राष्ट्र के लोगों को अपना मैसेज कन्वे कर दिया था कि भारत सैक्शंस का सामना करने के लिए एकजुट होकर तैयार है लेकिन वह घुटने नहीं टेकेगा, यह बात हमने स्पष्ट कर दी थी। अब उन राष्ट्रों के रुख में नर्मी आयी है, ऐसा हमको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं यह प्रश्न भारत सरकार से, उद्योग विभाग से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि सैक्शंस का जो असर होगा, भारत का उद्योग जगत उसका बड़ी दृढ़ता के साथ सामना करेगा, उसका

मुकाबला करेगा। लेकिन अफसोस यह हो रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में उद्योगों की दशा खराब हो गई है। उसकी प्रगति अवरुद्ध ही नहीं हुई बल्कि उसकी प्रगति में बाधा पड़ी है और उसकी इकानामी दर घटी है और इसके कारण उसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। मैं भारत सरकार के उद्योग मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सैक्शंस के साथ-साथ जो आंतरिक संकट उद्योगों पर आया हुआ है, वह चाहे बिजली के कारण हो, चाहे बिजली की दरों के कारण हो और चाहे मंदी के कारण हो, तो क्या ये कारण एक साथ इकट्ठे होने से आप जो औद्योगिक दर 8 प्रतिशत निश्चित कर रहे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए आप क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं, यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है? दूसरा भाग मेरा यह है कि जो स्ट्रैटजी आप बनाने जा रहे हैं इसके लिए जो थिंक टैंक आपने बनाया है, मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि सरकार ने एक थिंक टैंक बनाया है जो कि अच्छी बात है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि इस थिंक टैंक में अगर आप केवल सेक्रेटरीज को रखेंगे तो शायद यह थिंक टैंक पूरा अंजाम नहीं दे पाएगा। तो क्या आप उद्योग जगत से संबंधित लोगों को और इकनामिक एक्सपर्ट्स को भी इस थिंक टैंक में शामिल करने का प्रयास करेंगे?

श्री सिकन्दर बख्त: सर, मैं दूसरी सप्लीमेंटरी का जवाब देता हूं। पहला सप्लीमेंटरी is outside the scope of original question totally. थिंक टैंक की बात जो है वह हमने नहीं कही थी, बल्कि "फिक्की" ने अपनी एक स्टडी में कही है। जिस अखबार की खबर का हवाला आनरेबल मेंबर ने दिया है उसमें उसका जिक्र है। उसमें उन्होंने तफसील के साथ यह कहा है कि अगर हम एक मल्टी-डिसिप्लिनरी थिंक टैंक बनायेंगे तो हम सैंक्शंस के दबाव को कम कर सकते हैं। यह भी उन्होंने कहा है कि ऐक्शन रिसर्च कौंसिल बननी चाहिए, आल्टरनेटिव ग्लोबल चैनल्स होने चाहिए, उन्हें तलाश करना चाहिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आल्टरनेटिव सोर्सेज आफ इम्पोर्ट्स तलाश करना चाहिए यह भी उन्होंने कहा है। जहां तक हमारे कहने का ताल्लुक है हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। सैंक्शंस के दबाव को कम करने के लिए—अव्वल तो सैक्शंस के दबाव का जहां तक ताल्लुक है अब वह शिद्दत पिघल रही है, कम हो रही है। इसका सबूत यही है कि जून के आखिरी हफ्ते में और पहली जुलाई को हमारे चार प्रोजक्ट्स को वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी है जो [illegible] करीब एक मिलियन डालर्स से ज्यादा की [illegible]

इसके अलावा जो हम अपने तौर पर कदम उठा रहे हैं, मैं पहले यह बता दूं कि बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है जिसकी वजह से डिसबर्समेंट कम हो रहा है। इसकी वजह से सैक्शंस का दबाव कम होगा। ट्रेड सैक्शंस नहीं है, इसकी वजह से भी सैक्शंस का दबाव कम होगा। Disbursements against approved projects continue. U.S. Companies will seek new alternatives for the source of financing. इंडियन मार्किट का एक खास एट्रेक्शन है और हर मुल्क की नज़र इंडियन मार्किट की तरफ है, बावजूद सैंक्शंस के वह अपनी ट्रेड एक्टीविटीज़ जारी रखना चाहते हैं। जो बेसिक ह्युमेन नीड्ज़ हैं, उनके दायरे में सैंक्शंस का कोई असर नहीं है Basic human needs like Education, Health, sewarage, rural development, low income housing etc. इसलिए सैक्शंस की सिवियरिटी तो खत्म हो चुकी है। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि सैक्शंस का कोई असर है नहीं मगर यह ज़रूर कहूंगा कि सैक्शंस का असर कम हो रहा है।

† [illegible]

† [] Transliteration in Arabic Script.

کرنا چاہیئے اور ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ آلٹرنیٹیو سورسز آف امپورٹس تلاش کرنا چاہیئے یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ جہاں تک ہمارے بینک کا تعلق ہے ہم نے بہت سارے قدم اٹھائے ہیں۔ سینکشن کے دباؤ کو کم کرنے کے لئے اول تو سینکشن کے دباؤ کا جہاں تک تعلق ہے اب وہ شدت پگھل رہی ہے کم ہو رہی ہے۔ اسکا ثبوت یہی ہے کہ جون کے آخری ہفتے میں اور پہلی جولائی کو ہمارے چار پروجیکٹس کو ورلڈ بینک نے منظوری دی ہے اور قریب قریب ایک ملین ڈالرس سے زیادہ کی سینکشن ملی ہے۔

اس کے علاوہ جو ہم اپنے طور پر قدم اٹھا رہے ہیں، میں پہلے یہ بتا دوں کہ باہر کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے جسکی وجہ سے ڈسبرسمنٹ کم ہو رہا ہے اسکی وجہ سے سینکشن کا دباؤ کم ہوگا۔ ٹریڈ سینکشن نہیں ہے اسکی وجہ سے سینکشن کا دباؤ کم ہوگا۔

English

†[انڈین مارکیٹ کا ایک خاص اٹریکشن ہے اور ہر ملک کی نظر انڈین مارکیٹ کی طرف ہے، باوجود سینکشن کے وہ اپنی ٹریڈ ایکٹیویٹیز جاری رکھنا چاہتا ہیں۔ جو مسلک ہیومن بینڈز ہیں، انکے دائرے میں سینکشن کا کوئی اثر نہیں ہے۔

English

†[اس لئے سینکشن کی سوپریسی تو ختم ہو چکی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہونگا کہ سینکشن کا کوئی اثر ہے ہی نہیں مگر یہ ضرور کہونگا کہ سینکشن کا اثر کم ہو رہا ہے۔

श्री रामदास अग्रवाल: महोदय, औद्योगिक विकास दर जो पहले लगभग 8 प्रतिशत तक आई थी, वह इस समय 1997-98 में घट कर 4.9 प्रतिशत रह गई है और ओवर-आल 4.2 प्रतिशत है। हम सेंक्शंस का मुकाबला करेंगे, यह बात सही है लेकिन हमारा धरातल यदि मजबूत नहीं होगा तो हम सैंक्शंस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। धरातल को मजबूत करने के लिए उद्योग मंत्रालय क्या कदम उठाने जा रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री सभापति: इस का जवाब उन्होंने दे दिया है कि यह इस क्वेश्चन का पूरक नहीं है। और कोई सवाल हो तो बात अलग है।

SHRI S.R. BOMMAI: Sir, in spite of Government's declaration that the effect of sanctions will be on a massive scale, still it is a fact that after the explosion the exports have come down by 17 per cent. Many countries are not buying from us and foreign investment practically is nil after the explosion. I know that the World Bank has cleared such of the projects which have already been cleared or which are in the pipeline or which are going to help development of human resources. Particularly, in the field of education for Women and Child Development, they have cleared everything. I know, Sir, that projects will not be affected the climate nobody i- investment. I-

concessions given to NRIs, not a single big investment has come from them. Let the Minister name the NRIs or the countries which have made investment after the explosion and what is the export. That will give the indication.

श्री सिकन्दर बख्तः यह जो हमारे तरीके है इनवेस्टमेंट के, इनसे सैक्शंस का असर कम होगा। उनमें से एक तरीका यह भी है कि हम नॉन रेज़ीडेंट इंडियंस को भी एप्रोच कर रहे हैं ताकि उनकी तरफ से इनवेस्टमेंट आएं। हमारे दूसरे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्ज़ हैं, उनकी तरफ से भी हमने एप्रोच किया है लेकिन सिर्फ आपकी इत्तेला के लिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछले तीन महीनों में जो एफ०डी०आई० की क्यीयरेंसेज़ हुई हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि लोग आ रहे हैं, एप्लीकेशंस आ रही हैं। जून के महीने में 5954.97 करोड़ की अप्रूवल्ज़ दी गई हैं। यह जून, 1997 के मुकाबले में कितना ज्यादा है, पिछले जून में 2170.70 करोड़ की सैक्शंस दी गई थी। इस साल जून ही जून में और सब मिला कर तीन महीनों में अगर आप देखें तो तकरीबन 1500 करोड़ की सैंक्शंस मिली हैं। इसलिए यह कहना कि फॉरेन इनवेस्टर्ज़ की तवज्जो हमारी तरफ से हट गई है या कम हो गई है, यह गलत है।

درخواستیں آچکی ہیں، جون کے مہینے میں ۹۷-۵۹۵۴ کروڑ کی ایپروولز دی گئی ہیں - یہ جون ۱۹۹۷ کے مقابلہ میں کتنا زیادہ ہے، پچھلے جون میں ۷۰-۲۱۷۰ کروڑ کی سینکشن دی گئی تھی - اس سال جون ہی جون میں اور سب ملا کر تین مہینوں میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ۱۵۰۰ کروڑ کی سینکشن ملی ہے - اس لئے یہ کہنا کہ فارن انوسٹرز کی توجہ ہماری طرف سے ہٹ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، یہ غلط ہے ۔

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Chairman, Sir, there are two aspects to the whole issue. One is the direct sanctions by the countries concerned and direct investment by some of the companies. The other is the investment climate that has come about as a result of the sanctions.

Sir, the FICCI has pointed out—I do not know whether the Government endorses that survey or not—that the telecom sector would be affected. Then, there are several other sectors where, we know, there would definitely be an adverse impact on borrowings, interest rates, so on and so forth.

In this kind of a situation, what should we do? We are shouting from the rooftops that the country is united. There is no doubt that the country is united, so far as the immorality of the sanctions is concerned. But if we say that the country is united, it implies that we have to evolve a consensus to fight back the impact of sanctions. For this, there has to be some urgent consultations within the Government on the one hand, and with the Opposition on the other. Therefore, I

اشری سکندر بخت: یہ جو ہمارے طریقے ہیں انوسٹمنٹ کے، انسے سینکشن کا اثر کم ہوگا - ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نان ریزیڈنٹ انڈینس کو بھی اپروچ کر رہے ہیں تاکہ انکی طرف سے انوسٹمنٹ آئیں - ہمارے جو دوسرے فارن انسٹی ٹیوشنل انویسٹرس ہیں، انکی طرف سے بھی ہم نے اپروچ کی ہے لیکن صرف آپکی اطلاع کے لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے تین مہینوں میں جو ایف ڈی آئی کی کلیرنس ہوئی ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں

---

ation in Arabic Script.

would like to know whether the Government is going to announce or assure the House that some kind of consultations involving all the political parties would be there.

श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहब। अगेन अब तो यह दूसरे किस्म की बहस है। सवाल से तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जहां तक इस सरकार का ताल्लुक है यह करीब-करीब हर इम्पारटेंस के मसले पर, आपोजीशन से सलाह करती है, करना चाहती है और करती ही रही है। ऐसा मैं मानता हूं। आपको जवाब तो इतना ही दे सकता हूं।

†श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहब, अगेन - अब तो यह दूसरी किस्म की बहस है सवाल से तो कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन जहां तक इस सरकार का ताल्लुक है यह करीब करीब हर अहम मसले पर अपोजीशन से सलाह करती है - करना चाहती है और करती ही रही है - ऐसा मैं मानता हूं - आपको जवाब तो इतना ही दे सकता हूं -]

श्री नीलोत्पल बसु: आपकी आवाज में थोड़ा, मतलब फर्क हो गया है ...(**व्यवधान**)

श्री सिकन्दर बख्त: मेरी आवाज में फर्क इसलिए हुआ है सदर साहब कि सामने ...(**व्यवधान**) नीलोत्पल जी बैठे हैं।

†श्री सिकन्दर बख्त: मेरी आवाज में फर्क इसलिये हुआ है सदर साहब कि सामने ... नीलोत्पल जी बैठे हुये हैं -]

श्री नीलोत्पल बसु: यह इंडिपेंडेंट सर्वे बता रहा है कि कम से कम एक इम्पारटेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट होगा। आप कैसे बोल रहे हैं कि इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा ...((**व्यवधान**)

श्री सिकन्दर बख्त: इन्होंने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था ...(**व्यवधान**) देखिए, जनरली स्पीकिंग 1998-99 में सैंक्शन का असर मामूली होगा। मैंने शुरू में ही यह कह दिया है कि यह कहना कि कुछ नहीं होगा तो गलत होगा। लेकिन जहां तक टेलीकाम सेक्टर की बात कही है इन्होंने, दुरुस्त कही है कि टेलीकाम सेक्टर अफेक्ट होगा।

†श्री सिकन्दर बख्त: इन्होंने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था ... "व्यवधान" देखिए, जनरली स्पीकिंग 1998-99 में सैंक्शन का असर मामूली होगा - मैंने शुरू में ही यह कह दिया है कि यह कहना कि कुछ नहीं होगा तो गलत होगा - लेकिन जहां तक टेलीकाम सेक्टर की बात कही है इन्होंने, दुरुस्त कही है कि टेलीकाम सेक्टर अफेक्ट होगा -]

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Sir, the suggestion that a core group should be constituted to study in-depth the effect of these sanctions, I think, is very important. The Government's response that they have set up a co-ordinating committee consisting of Government Secretaries, I think, is not adequate. In regard to the effect of the sanctions, most of the time, the Government's response is that it may be of the order of one billion dollars or two billion dollars or three billion dollars. That is not the main point. As my colleague here mentioned, the sentiment has been so badly affected that it has had an enormous impact on the industry in India and it is going to have a continuing effect on the investment climate, so long as we do not counter the effect of the sanctions that have been imposed.

My suggestions is that—I hope the hon. Minister would agree to it—the committee should be expanded to include certain experts who are available with the

various trade organisations like the FICCI, the CII, etc. They have many experts. They can be included in this Committee of Secretaries so that they can really study the whole effect of the sanctions on the country.

SHRI SIKANDER BAKHT: Sir, I was trying to find out what is meant by 'the core group of Secretaries'. I am afraid, the hon. Member has strayed from the FDI aspect to the disinvestment process. The core group is one link in the whole process of disinvestment. It is not all. Ultimately, the decision lies with the Cabinet.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: My question was not on disinvestment. It was on the adverse climate created because of the sanctions against India. So, it has nothing to do with disinvestment.

SHRI SIKANDER BAKHT: You said something about the Core Committee.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: The Core Committee of Secretaries was constituted as a think-tank to counter its adverse effects. I said, "Expand it because this is not an adequate response."

श्री रामदास अग्रवाल: प्रारंभ में मैंने यह बात पूछी थी।

SHRI SIKANDAR BAKHT: Well, I think, I have not understood your question. I beg your pardon. मैं अर्ज करूंगा आप से कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, वह कदम बहुत साफ हैं। अब गवर्नमेंट इस इम्पेक्ट को कम करने के लिए क्या कर रही है, वह मैं आप लोगों को बता सकता हूं।

In 1998-99 the industrial production is not likely to be affected by the sanctions.

मैंने वह जुबानी पहले किसी के जवाब में कहा था।

It can be stated that the sanctions with regard to foreign aid are expected in most cases.

वह मैं दोहरा चुका हूं, कहिए तो फिर दोहरा दूं कि कौन-कौन से केसेस में फारेन एड इफेक्टेड नहीं होती है। The severity of the sanctions is now waning.

श्री नीलोत्पल बसु: आज भी एक पेपर में लाइट कॉम्बेट एअरक्राफ्ट वगैरा के बारे में न्यूज है। अब यह अलग बात है कि आप के पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हाउस को मिसलीड तो मत कीजिए।

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: My response was not on the details. My response was that the think-tank that has been created, is inadequate to deal with this problem. They should widen the scope of this think-tank so that you get the benefit of a wider advice, a much more indepth advice, taking into consideration the views expressed by industry also which is largely suffering from its consequences.

SHRI SIKANDER BAKHT: I have already said that the idea of the think-tank was not that of the Government. It was the idea of the FICCI. We are prepared to accept it and the suggestion of the hon. Member that we should expand whatever machinery or mechanism we have for this.

SHRI JANARDHANA POOJARY: In 1985-86, the growth rate in the industrial sector was 12 per cent. In 1986-87 it came down to 7.1 per cent. In 1997-98 it has come down to 4.2 per cent. Sir, in view of the sanctions imposed against India, has the Government of India identified the fall-out of the sanctions? We are getting assistance from the World Bank and other multilateral institutions for our purpose. Has the Government identified any projects which are going to be affected by withdrawal of the assistance by the World Bank and other multilateral institutions? If so, which are the projects, the main porjects? Can you bring them to the notice of the House?

SHRI SIKANDER BAKHT: The Government is approaching the general problems and not specific problems.